जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 15 संख्याः 265 प्रभात हिण्डौन सिटी, मंगलवार 25 जुलाई, 2023 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

असम में ज़हर से मरे हजारों पक्षियों के एक वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। वन विभाग ने मृत पक्षियों के अवशेष जांच के लिए भिजवाए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, छब्बीस जून को बारपेटा जिले के जानिया गाँव में धान में विष मिलाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, नागर अली और सागर अली की पहचान कर ली गई है। रिपोर्ट के अनुसार इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पक्षियों की सामूहिक मृत्यु पर लोगों का ध्यान तब गया जब एक पर्यावरणविद् ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मरने वाले पक्षी हैं ''स्पॉटेड डव'' (चित्तीदार फाख्ता), जो मूलतः एशिया, खासकर भारत में मिलते हैं और इस क्षेत्र में तो इनकी संख्या अच्छी खासी है। स्थानीय अलाभकारी संस्था, अरण्यक के सैक्रेटरी जनरल बिभब कुमार तालुकदार ने कहा, ''विष की वजह से इतने सारे पक्षियों का मरना एक दुखदायी घटना है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि गांवों में निगरानी बढ़ाएं तथा लोगों में जागरुकता पैदा करें।'' वीडियो के अनुसार, पक्षियों को फसल खाने से रोकने के लिए विष डाला गया। तालुकदार ने कहा कि ''यहां इस मौसम की प्रमुख फसल चावल है और भोजन के लिए पक्षियों का खेतों में आना बेहद आम है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए फसल पर विष डालना अतिवादी कदम है।'' उन्होंने कहा कि, ये पक्षी इकोसिस्टम में अहम् भूमिका निभाते हैं। कई प्रकार के कीटों और चूहों को खाकर ये फसलों को बचाते हैं। यही नहीं, कई पौधों के परागण और उनके रीजनरेशन में भी मदद करते हैं। खेतों में इन पक्षियों की मौजूदगी से ना केवल इकोसिस्टम संतुलित रहता है बल्कि इससे जैवविविधता को भी प्रोत्साहन मिलता है और फसल का भी बचाव होता है।

एक लाल डायरी ने हिला कर रख दिया है गहलोत सरकार को

डायरी किसके पास है और इसमें क्या है? ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब जयपुर से लेकर दिल्ली तक का मीडिया ढूंढ रहा है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। ''लाल डायरी'' ने गहलोत सरकार को हिला कर रख दिया है।

यह डायरी किसके पास है तथा इसमें क्या है? जयपुर से लेकर दिल्ली तक के पूरे मीडिया-जगत को ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

इस समय राजस्थान के सबसे चर्चित व्यक्ति राजेन्द्र गुढ़ा द्वारा राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार, जिसका विवरण कथित लाल डायरी है, का मुद्दे उठाये जाने के बाद, भाजपा ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया है।

भाजपा ने संसद में गहलोत एवं उनकी सरकार के खिलाफ तख्तियाँ लहराई तथा कहा कि अशोक गहलोत के शासन में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य बन गया है।

- चर्चा है कि, लाल डायरी में अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार का विस्तृत ब्यौरा है।
- भाजपा सांसदों ने संसद में गहलोत व उनकी सरकार के खिलाफ तख्तियाँ लहराईं तथा आरोप लगाया कि, गहलोत के राज में राजस्थान की महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध हुए हैं।
- जब अशोक गहलोत ने अपमानजनक तरीके से गुढ़ा को मंत्री पद से हटाया तो, उन्हें समझना चाहिए था कि, इसका अंजाम क्या हो सकता है। इस चुनावी वर्ष में बेहतर होता उन्हें बुला कर शांत किया जाता।

भाजपा ने यह भी पूछा कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले में प्रियंका गांधी खामोश क्यों है।

जहाँ भाजपा संसद में राजस्थान पर चर्चा कराना चाहती है, वहीं लाल डायरी के तथाकथित अस्तित्व के बाद, कांग्रेसजन बैकफुट पर आ गये हैं।

धर्मेन्द्र राठौड़ कथित रूप से गहलोत के ''बैग मैन'' हैं। जहाँ गहलोत अपनी सौदेबाजी के साक्ष्यों एवं प्रमाणों को छिपाने की कोशिश में हैं, वहीं सब लोग यह कयास लगा रहे हैं कि उस डायरी में क्या है।

जब अशोक गहलोत ने राजेन्द्र गुढ़ा को बड़े रूखे तरीखे से मंत्रिमण्डल से बर्खास्त किया था, उस समय उनको यह सोचना-समझना चाहिये था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इस चुनावी वर्ष में, बेहतर विकल्प यह रहा होता कि मुख्यमंत्री उन्हें बुलाते तथा समझाबुझा कर उन्हें शांत एवं संतुष्ट करते।

लेकिन न तो इसके साथ ही गुढ़ा के आरोप समाप्त हो रहे हैं और गहलोत के भ्रष्टाचार की चर्चाएं, जिसे राज्य का मीडिया जोरदार तरीके से सामने नहीं ला रहा है।

''मिसिंग'' विदेश मंत्री और ''सीक्रेसी'' की सनक ने चीन की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया

चीन के विदेश मंत्री चिन को 25 जून के बाद से किसी ने भी नहीं देखा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। बीजिंग अटकलों को नहीं रोक पाया है क्योंकि संदेहवादी लोग इन सरकारी बयानों पर संदेह कर रहे हैं कि कुछ अज्ञात स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों के कारण देश के विदेश मंत्री चिन गांग लम्बे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं।

कूटनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि हाई प्रोफाइल विदेश मंत्री के नज़र नहीं आने को लेकर बरती जा रही गोपनीयता देश के राजनैतिक तंत्र से जुड़े संदेहों को और भी बढ़ा रहे हैं।

- विदेश मंत्री कहां हैं, इस पर तो चीन ने कुछ नहीं कहा, पर इन अफवाहों को अवश्य बढ़ावा दिया कि, वे बीमारी के कारण सामने नहीं आ रहे हैं।
- चिन को आखिरी बार 25 जून को देखा गया था, तब वे रूस, वियतनाम व श्रीलंका के राजनयिकों से मिले थे।
- उसके बाद उनके जितने भी निर्धारित कार्यक्रम थे, उनमें से अधिकतर कार्यक्रम उनकी ''अनुपस्थिति'' बता कर रद्द कर दिए गए।
- विदेश मंत्री की गुमशुदगी को पश्चिमी जगत व विदेश नीति विशेषज्ञ अशुभ संकेत मान रहे हैं।

चीनी कूटनीति के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण समय है। पिछले महीने में कई देशों के वर्तमान व भूतपूर्व नेताओं ने चीन के दौरे किये हैं लेकिन देश के विदेश मंत्री साफ तौर पर अनुपस्थित ही रहे हैं।

''साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट'' के अनुसार, क्विन, जो देश का चेहरा माने जाते हैं, 25 जून से ही लोगों की नजरों से दूर हैं तथा वे अति महत्वपूर्ण अवसरों, जैसे इंडोनेशिया में हुई विदेश मंत्रियों की रीजनल मीटिंग तथा वरिष्ठ अमेरिकन नेताओं द्वारा की गईं चीन यात्राओं आदि के दौरान भी अनुपस्थित ही रहे।

बीजिंग ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वे कहाँ हैं। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे संदेह एवं अटकलों के बावजूद, केवल इतना ही बताया जा रहा है कि वे किन्हीं अज्ञात ''स्वास्थ्य कारणों'' से गैर हाजिर हैं।

कूटनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि चिन, जिनका चयन सिर्फ सात माह पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था, की लंबे समय से चली आ रही अनुपस्थिति बहुत बड़ी परेशानी एवं लज्जा का विषय बनती जा रही प्रतीत हो रही है।

उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी अनुपस्थिति से संबंधित गोपनीयता को बीजिंग द्वारा समाप्त न करने से चीन के अपारदर्शी निर्णयों के बारे में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

युन सुन, जो वाशिंगटन के ''स्टिम्सन सेन्टर'' पर चीनी कार्यक्रमों के निदेशक हैं, ने कहा है कि बीजिंग का संक्षिप्त एवं रूखा जवाब विश्वास के योग्य नहीं है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, चिन अंतिम बार उस समय सबके सामने आये थे, जब 25 जून को वे रूस, वियतनाम

(शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है?
ऑटोमेटिक
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

'स्पीकर के अयोग्यता नोटिस विवाद में तीन सप्ताह में जवाब दे केन्द्र सरकार'

जयपुर, 24 जुलाई (का.सं.)। विधानसभा स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी द्वारा पायलट गुट के 18 विधायकों को दिए गए नोटिस से सम्बंधित मामलों पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। गौरतलब है कि स्पीकर ने सभी विधायकों को 7 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा था कि उन्हें विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य क्यों ना घोषित किया जाए? विधायकों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी। इस रोक के खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जो अभी भी लम्बित है। जैसा कि विदित है कि वर्तमान मामले में स्पीकर द्वारा विधायकों को नोटिस दिए जाने से सम्बंधित प्रक्रिया के कानून

- राजस्थान हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट के विधायकों के मामले में स्पीकर के अयोग्यता नोटिस विवाद में केन्द्र सरकार द्वारा तीन साल में भी जवाब नहीं देने पर आश्चर्य जताया और पुनः नोटिस जारी किया।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

एन.डी.ए. के घटक दलों से ''क्लस्टर'' मीटिंग करेंगे प्र.मंत्री मोदी

मीटिंग्स की शुरूआत 31 जुलाई से होगी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। विपक्ष के एकता प्रयासों का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने 18 जुलाई को एन.डी.ए. की समानांतर बैठक बुलाई और अब भाजपा अगले स्तर पर पहुंच गई है जहां पार्टी एन.डी.ए. सांसदों से ''क्लस्टर मीटिंग्स'' बैठक करेगी। इन बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रात्रिभोज होगा।

आमतौर पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप झेलती भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस छवि को धोना चाहती है।

समूहों की बैठकें 31 जुलाई से आरंभ होगी जब उत्तर प्रदेश (ब्रज-कानपुर-बुंदेलखंड), पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ बैठक के लिए बुलाया गया है। पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केन्द्रिय मंत्री नितिन गडकरी पहली बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि दूसरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह होंगे।

दूसरी बैठक 2 अगस्त को होगी जब उत्तर प्रदेश में काशी-गोरखपुर और अवध के सांसदों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के सांसदों को बुलाया गया है। केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, महेन्द्रनाथ पांडे, प्रहलाद जोशी और वी. मुरलीधरन को इन बैठकों की मेजबानी सौंपी गई है।

बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सांसद 3 अगस्त को प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के सांसद 8 अगस्त को मिलेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात-दादरा-नगर हवेली और दमण-दीव के सांसदों को 9 अगस्त को बुलाया गया है। उत्तर पूर्व में भाजपा और एन.डी.ए. के भागीदारों की बैठक की तिथि तय नहीं हुई है।

- ये मीटिंग 9 अगस्त तक चलेंगी। हर दिन अलग-अलग राज्यों के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रमुख केन्द्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
- मीटिंग्स के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी सहयोगी दलों के सभी सांसदों को स्नेह भोज देंगे।

नए वकीलों को स्टाइपैंड देने से सरकार का इन्कार

जयपुर, 24 जुलाई (का.सं.)। प्रदेश में वकीलों के वेलफेयर फंड में अंशदान नहीं देने और नए वकीलों को स्टाइपैंड देने की मांग से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर युवा वकीलों को स्टाइपैंड देने पर अपनी असहमति जताई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल (ए.ए.जी.) आर.पी. सिंह की ओर से पेश जवाब में, विधि विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया कि, वकीलों को स्टाइपैंड देने के संबंध में वित्त विभाग से सहमति मांगी गई थी, लेकिन वित्त विभाग का कहना है कि मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व गुजरात में वकीलों को स्टाइपैंड देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए यहां पर भी वकीलों को स्टाइपैंड नहीं दे सकते।

- राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि, पड़ौसी राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में वकीलों को स्टाईपैंड नहीं मिलता है, हम भी नहीं देंगे।

ज्ञातव्य है कि, जन घोषणा पत्र 2019-20 के अनुसार अधिवक्ता समुदाय के प्रतिनिधियों से बात करके एडवोकेट्स पेंशन, इंश्योरेंस व स्टाइपैंड के संबंध में राज्य सरकार को बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान जोधपुर से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर प्रार्थी को एक सप्ताह में जवाब देने का मौका देते हुए मामले की सुनवाई एक अगस्त के लिए तय की है। चीफ जस्टिस ए.जी. मसीह व जस्टिस समीर जैन की

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कर्नाटक हाई कोर्ट के छः जजों को जान से मारने की धमकी

बैंगलुरु, 24 जुलाई। कर्नाटक हाईकोर्ट के छह जजों को जान से मारने की धमकी दी गई है। दुबई गैंग की तरफ से भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि उनकी जान बचने की केवल एक ही सूरत है कि पाकिस्तान के बैंक में 50 लाख रुपये तुरंत जमा करा दिए जाए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

- दुबई गैंग की तरफ से भेजे गए वॉट्सऐप मैसेज में कहा गया है कि, जजों की जान बचने की केवल एक ही सूरत है कि, पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक में 50 लाख रुपये तुरंत जमा करा दिए जायें।

हाईकोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के मुरलीधर की शिकायत पर बेंगलुरु की साइबर क्राइम पुलिस ने दर्ज

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सरकार सभी राज्यों में अपराधों पर बहस चाहती है केवल मणिपुर पर नहीं

विपक्ष केवल मणिपुर में हिंसा व अपराध पर बहस चाहता है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जुलाई। विपक्षी गठबंधन आई.एन.डी.आई.ए. अर्थात ''इंडिया'' और सत्तारूढ़ एन.डी.ए. के बीच उस बात की लड़ाई गहरा रही ह कि लोगों के दिमाग पर कौन ज्यादा गहरा और स्थायी प्रभाव डालता है। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों पर विपक्ष और सरकार के बीच हुई तीखी बहस के बीय संसद के दोनों सदन स्थगित हो गए।

अगले साल आम चुनाव के मैदान में उतरने से पहले दोनों गठबंधन संसद में जोर आजमाइश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष पूरी ताकत लगा रहा है कि नवगठित इंडिया गठबंधन को अपने अनुसार मोड़ ले जबकि विपक्षी गठबंधन इस पर मजबूती से कायम है कि वह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा का अपना उद्देश्य पूरा करेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से वक्तव्य दिलवाएगा।

एन.डी.ए. प्रधानमंत्री को ऐसे प्रहारों से बचाना चाहता है जिनसे उनके पहले से धूमिल छवि और बिगड़े जबकि इंडिया उनकी छवि को जनता के सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। दुविधा को सुलझाने में असफलता के कारण संसद में दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उत्पन्न हुआ है।

- इस चाहत की दुविधा में फंसी संसद तथा कार्यवाही दिन भर स्थगित रही।
- विपक्ष का आरोप है कि, एन.डी.ए. नॉर्थ ईस्ट में हिंसा को ''डिफ्यूज़'' (हल्का) करना चाहती है, सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से जोड़ कर देखने के प्रयास से।
- विपक्ष ने रूल 276 के तहत मामला उठाया संसद में, जिसके अंतर्गत सभी अन्य मामलों पर बहस सस्पैंड करके मणिपुर की स्थिति पर बहस करना चाहता है विपक्ष।
- एन.डी.ए. के सांसदों ने धारा 176 के तहत बहस की मांग रखी है, जिसके अंतर्गत अल्पकालीन बहस ही संभव है।
- विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में मणिपुर पर बहस के लिए 27 स्थगन प्रस्ताव रखे, वहीं एन.डी.ए. के सांसदों ने मणिपुर के साथ विपक्ष शासित राज्यों, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चर्चा कराने के लिये 11 नोटिस दिए।

विपक्षी पार्टियों में इंडिया के झंडे तले संयुक्त विरोध करने के बाद राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए 27 स्थगन प्रस्ताव दिए। एन.डी.ए. के सांसदों के 11 नोटिस देकर मांग की कि विपक्ष शासित राज्यों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर चर्चा की जाए- राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और केरल तथा मणिपुर हिंसा पर भी चर्चा की जाए।

इंडिया स्पष्ट रूप से मणिपुर की स्थिति पर अलग से चर्चा करना चाहता है क्योंकि राज्य में 3 मई से जातीय हिंसा जारी है। एन.डी.ए. इस उत्तर पूर्वी राज्य के मामले को हलका करने के लिए विपक्ष शासित राज्यों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर चर्चा करना चाहता है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)